

श्री क्षात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन (SKPF) एवं WINCOMPETE- संयुक्त टेस्ट सीरीज - 2026

समय: 2:00 घण्टे |

| अधिकतम अंक: 300

विषय: राज्य राजव्यवस्था (राज.)

टेस्ट संख्या: [16]

अभ्यर्थी का नाम: _____

अनुक्रमांक (Roll No.): _____

परीक्षा केंद्र _____

हस्ताक्षर अभ्यर्थी: _____

हस्ताक्षर वीक्षक: _____

परीक्षार्थियों के लिए निर्देश

1. इस प्रश्न-पुस्तिका में कुल 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के चार विकल्प (A, B, C, D, E) दिए गए हैं।
2. प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक निर्धारित हैं।
3. **नकारात्मक अंकन (Negative Marking):** प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा।
4. OMR उत्तर पत्रक में पाँच विकल्प (A, B, C, D, E) में एक का अंकन करना है। यदि आप किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते हैं, तो अनिवार्य रूप से विकल्प 'E' को अंकित करें।
5. यदि अभ्यर्थी किसी प्रश्न को हल नहीं करता है और विकल्प 'E' को भी अंकित नहीं करता है, तो उस प्रश्न के लिए भी 1/3 भाग (1 अंक) काटा जाएगा। (नवीनतम RPSC नियम)
6. कच्चे कार्य (Rough work) के लिए स्थान इस पुस्तिका के अंत में दिया गया है।
7. अपने रोल नम्बर और अन्य विवरण केवल निर्धारित स्थान पर ही लिखें।

प्रश्न 1:

कथन I : अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान है, तथा सातवें संविधान संशोधन 1956 द्वारा एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है।

कथन II: राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा राजमुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा होती है और वह संविधान के अनुच्छेद 156(3) के अनुसार राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है, जिसकी सामान्य अवधि 5 वर्ष है।

कथन III: राज्यपाल को पद ग्रहण करते समय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष तीसरी अनुसूची में निर्धारित प्रारूप पर शपथ लेनी होती है।

उपरोक्त में से कौनसा/कौनसे कथन/कथन समूह सत्य है :

- A) केवल 1 और 2
- B) केवल 2 और 3
- C) केवल 1 और 3
- D) केवल 1

प्रश्न 2:

कथन: अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल की क्षमादान शक्ति राष्ट्रपति की तुलना में अधिक सीमित है, क्योंकि राज्यपाल मृत्युदंड को पूरी तरह माफ करने या सैन्य न्यायालय (कोर्ट मार्शल) के दंड पर हस्तक्षेप करने की शक्ति नहीं रखता है।

कारण: राज्यपाल राज्य की कार्यकारी शक्ति के विस्तार वाले विषयों तक ही क्षमादान सीमित रखता है, और संविधान निर्माता संघ बनाम राज्य न्यायपालिका के शक्ति संतुलन को बनाए रखना चाहते थे।

- A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या करता है
- B) A और R दोनों सत्य हैं परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं करता है
- C) A सत्य है परंतु R असत्य है
- D) A असत्य है परंतु R सत्य है

प्रश्न 3:

कथन: राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के सत्र को आहूत और सत्रावसान करने की शक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह से संचालित होती है, किंतु त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में मुख्यमंत्री नियुक्ति का स्वविवेक संविधानसम्मत् माना गया है।

निष्कर्ष I : राज्यपाल विधानमंडल के विघटन का निर्णय पूरी तरह से अपने व्यक्तिगत राजनीतिक आकलन के आधार पर बिना किसी मंत्री-परामर्श के कर सकता है।

निष्कर्ष II : नबाम रेबिया वाद (2016) के अनुसार राज्यपाल को सदन के सत्र आहूत करने में मंत्रिपरिषद की राय की अवहेलना करने का कोई स्वविवेक नहीं है।

- A) केवल निष्कर्ष I सत्य है
- B) केवल निष्कर्ष II सत्य है
- C) निष्कर्ष I और II दोनों असत्य हैं
- D) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 4: सुमेलित कीजिये

सूची I : राज्यपालों से संबंधित ऐतिहासिक व विवादास्पद घटनाक्रम

- a) प्रथम राष्ट्रपति शासन (राजस्थान, 1967)
- b) दूसरा राष्ट्रपति शासन (1977)
- c) तीसरा राष्ट्रपति शासन (1980)
- d) चौथा राष्ट्रपति शासन (1992-1993)

सूची II : तत्कालीन राजनैतिक/वैधानिक संदर्भ

- I) जनता पार्टी केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा चुनाव परिणामों के आधार पर बर्खास्तगी
- II) भैरोसिंह शेखावत सरकार की बर्खास्तगी और बाबरी मस्जिद विध्वंसोत्तर राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य
- III) मोहनलाल सुखाड़िया के समय त्रिशंकु सरकार गठन विवाद (54 दिन)
- IV) भैरोसिंह शेखावत की लोकप्रिय सरकार की प्रथम बार बर्खास्तगी (जनता पार्टी काल)

- A) a-III, b-I, c-IV, d-II
- B) a-I, b-III, c-II, d-IV
- C) a-IV, b-II, c-I, d-III
- D) a-III, b-II, c-IV, d-I

प्रश्न 5:

असंगत कथन की पहचान करें :

- A) अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल बनने के लिए भारत का नागरिक होना और 35 वर्ष की न्यूनतम आयु पूरी करना अनिवार्य अहर्ताएं हैं।
B) अनुच्छेद 158(2) के अनुसार राज्यपाल संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा।
C) राज्यपाल को संसद विधि द्वारा या संविधान की दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं जिनमें उसकी पदावधि के दौरान उसके लाभ के लिए परिवर्तन किया जा सकता है।
D) अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपाल अपने कर्तव्यों के पालन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है।

प्रश्न 6:

अनुच्छेद 200 के तहत जब राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो पॉकेट वीटो की वैधानिक अनिश्चितता और राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने के प्रावधान संघीय व्यवस्था के संतुलन को प्रभावित करते हैं।

उपरोक्त परिच्छेद के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक तार्किक निष्कर्ष है?

- A) राज्यपाल धन विधेयक को भी अनिश्चितकाल के लिए रोक सकता है।
B) संविधान में राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने की कोई समय-सीमा निर्धारित न होने से व्यावहारिक रूप से अनिश्चितकालीन निलंबन या पॉकेट जैसा प्रभाव उत्पन्न हो जाता है।
C) राज्य विधानमंडल द्वारा दोबारा पारित विधेयक पर राज्यपाल राष्ट्रपति आरक्षण के लिए बाध्य है।
D) राज्यपाल आत्यंतिक वीटो का प्रयोग मंत्रिपरिषद् की इच्छा के विरुद्ध हमेशा कर सकता है।

प्रश्न 7:

कथन I : राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सदनों या संयुक्त सत्र को संबोधित कर सकता है (अनुच्छेद 175-176) तथा लंबित विधेयकों पर संदेश भेज सकता है।

कथन II: राज्यपाल विधान परिषद (यदि अस्तित्व में हो) में साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन और समाजसेवा के क्षेत्र से 1/6 सदस्यों का मनोनयन करता है।

कथन III: संविधान (104वां संशोधन) अधिनियम 2019 द्वारा आंग्ल-भारतीय समुदाय का मनोनयन समाप्त कर दिया गया है जो विधान सभा में लागू होता है।

उपरोक्त में से कौनसा/कौनसे कथन/कथन समूह सत्य है :

- A) केवल 1 और 2
B) केवल 2 और 3
C) केवल 1, और 3
D) केवल 2

प्रश्न 8:

कथन: अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति तब प्राप्त होती है जब विधानमंडल सत्र में नहीं होता और तत्काल कार्रवाई आवश्यक हो।

कारण: डी.सी. वाधवा बनाम बिहार राज्य (1987) वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अध्यादेश बनाने की शक्ति विधायी शक्ति के विकल्प के रूप में बार-बार उपयोग करना संवैधानिक धोखाधड़ी नहीं है।

- A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या करता है
B) A और R दोनों सत्य हैं परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं करता है
C) A सत्य है परंतु R असत्य है
D) A असत्य है परंतु R सत्य है

प्रश्न 9:

कथन: राज्यपाल के स्वविवेक के संबंध में संवैधानिक और परिस्थितिजन्य श्रेणियां स्पष्ट हैं।

निष्कर्ष I : असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के राज्यपालों द्वारा छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिला परिषदों के रॉयल्टी राजस्व का निर्धारण सांविधिक स्वविवेक का उदाहरण है।

निष्कर्ष II : त्रिशंकु विधानसभा में सबसे बड़े दल या पूर्व-निर्वाचित गठबंधन को आमंत्रित करना संवैधानिक स्वविवेक की श्रेणी में आता है।

- A) केवल निष्कर्ष I सत्य है
B) केवल निष्कर्ष II सत्य है
C) निष्कर्ष I और II दोनों असत्य हैं
D) केवल I व II का संमिश्रण

प्रश्न 10:सुमेलित कीजिये

सूची I : राजस्थान के प्रमुख राज्यपाल

- a) सरदार गुरुमुख निहाल सिंह
- b) डॉ. संपूर्णानंद
- c) रघुकुल तिलक
- d) कलराज मिश्र

सूची II : विशिष्ट कार्यकाल / ऐतिहासिक संदर्भ

- I) केंद्र-राज्य संबंधों और राज्यपाल की राजनैतिक निष्पक्षता पर व्यापक बहस (आपातकालोत्तर काल)
- II) राजस्थान के प्रथम राज्यपाल (1 नवंबर 1956 से)
- III) उच्च शिक्षा सुधार और समकालीन विधायी संदर्भों का समन्वय
- IV) शिक्षाविद पृष्ठभूमि एवं प्रथम बड़े प्रशासनिक संक्रमण का अवलोकन

- A) a-II, b-IV, c-I, d-III
- B) a-I, b-II, c-III, d-IV
- C) a-IV, b-I, c-II, d-III
- D) a-III, b-IV, c-I, d-II

प्रश्न 11:

असंगत कथन की पहचान करें :

- A) अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा।
- B) सातवें संविधान संशोधन 1956 द्वारा संसद को दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति दी गई है।
- C) उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय (Court of Record) नहीं होता है क्योंकि उसके निर्णय अन्य अधीनस्थ अदालतों पर बाध्यकारी नहीं होते हैं।
- D) उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाती है।

प्रश्न 12:

कथन: राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जोधपुर में 29 अगस्त 1949 को स्थापित की गई थी और सत्यनारायण राव समिति की संस्तुतियों पर 1958 में शाखाएं समाप्त कर दी गईं।

कारण: 31 जनवरी 1977 को स्थायी जयपुर पीठ की पुनर्स्थापना प्रशासनिक सुगमता और मुकदमों के भार के कारण की गई थी।

- A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या करता है
- B) A और R दोनों सत्य हैं परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं करता है
- C) A सत्य है परंतु असत्य है

D) A असत्य है परंतु R सत्य है

प्रश्न 13:

कथन: उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

निष्कर्ष I : उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति हेतु कम से कम 10 वर्ष का न्यायिक पद या 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना अनिवार्य है।

निष्कर्ष II : उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक पद धारण करता है।

- A) केवल निष्कर्ष I सत्य है
- B) केवल निष्कर्ष II सत्य है
- C) निष्कर्ष I और II दोनों असत्य हैं
- D) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 14:सुमेलित कीजिये

सूची I : उच्च न्यायालय की अधिकारिता एवं प्रावधान

- a) अभिलेख न्यायालय
- b) रिट अधिकारिता का विस्तार
- c) अधीनस्थ अदालतों पर अधीक्षण
- d) जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति परामर्श

सूची II : संबंधित अनुच्छेद

- I) अनुच्छेद 227
- II) अनुच्छेद 233
- III) अनुच्छेद 215
- IV) अनुच्छेद 226

- A) a-III, b-IV, c-I, d-II
- B) a-I, b-II, c-III, d-IV
- C) a-II, b-I, c-IV, d-III
- D) a-IV, b-III, c-II, d-I

प्रश्न 15:

असंगत कथन की पहचान करें :

- A) अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है।
- B) अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के लिए ही रिट जारी कर सकता है, सांविधिक अधिकारों के लिए नहीं।
- C) उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता विवेकीय (Discretionary) प्रकृति की है।

D) बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट अवैध निरोध के विरुद्ध जारी की जाती है।

प्रश्न 16:

अधीनस्थ न्यायपालिका में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है, जबकि अधीनस्थ न्यायिक सेवा के अन्य सदस्यों की नियुक्ति RPSC और उच्च न्यायालय के परामर्श से होती है, और प्रशासनिक नियंत्रण पूर्णतः उच्च न्यायालय के पास है। उपरोक्त परिच्छेद के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है?

- A) जिला न्यायाधीशों की पोस्टिंग में कार्यपालिका का अंतिम नियंत्रण होता है।
- B) अनुच्छेद 235 के तहत अधीनस्थ न्यायपालिका पर पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण उच्च न्यायालय में निहित है।
- C) सिविल जज की नियुक्ति केवल राज्यपाल अपने स्वविवेक से करता है।
- D) जिला न्यायाधीश बनने हेतु 5 वर्ष का अनुभव पर्याप्त है।

प्रश्न 17:

कथन I : सत्र न्यायालयों द्वारा दिए गए मृत्युदंड की उच्च न्यायालय द्वारा संपुष्टि (Confirmation) दं.प्र.सं. की धारा 366 के तहत आवश्यक होती है।

कथन II: एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ (1982) वाद में न्यायाधीशों के स्थानांतरण पर आधारभूत व्याख्या दी गई थी।

कथन III: ई-कोर्ट्स प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान में वर्चुअल सुनवाई और NJDG इंटीग्रेशन लागू है। उपरोक्त में से कौनसा/कौनसे कथन/कथन समूह सत्य है :

- A) केवल 1 और 2
- B) केवल 2 और 3
- C) केवल 1 और 3
- D) केवल 2

प्रश्न 18:

कथन: उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता प्रादेशिक क्षेत्राधिकार या वाद-हेतु (Cause of action) उद्भूत होने के क्षेत्र तक सीमित है।

कारण: उच्चतम न्यायालय का प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र संपूर्ण भारतवर्ष पर विस्तारित है, जबकि उच्च

न्यायालय का क्षेत्र राज्य/संघ क्षेत्र तक सीमित रहता है।

- A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या करता है
- B) A और R दोनों सत्य हैं परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं करता है
- C) A सत्य है परंतु R असत्य है
- D) A असत्य है परंतु R सत्य है

प्रश्न 19:

कथन: अधीनस्थ न्यायालयों के प्रशासनिक नियंत्रण में उच्च न्यायालय की भूमिका न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मूल आधार है।

निष्कर्ष I : जिला न्यायपालिका राज्य की न्याय प्रणाली की धरातलीय इकाई है।

निष्कर्ष II : कार्यपालिका द्वारा जिला न्यायाधीशों के प्रमोशन पर सीधे आदेश जारी किए जा सकते हैं।

- A) केवल निष्कर्ष I सत्य है
- B) केवल निष्कर्ष II सत्य है
- C) निष्कर्ष I और II दोनों असत्य हैं
- D) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 20:

संविधान का अनुच्छेद 214 राज्य न्यायपालिका की रीढ़ है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म/तथ्य उच्च न्यायालय के संबंध में असत्य है?

- A) न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष है।
- B) महाभियोग समतुल्य प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से पारित होती है।
- C) मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति CJI और राज्यपाल के परामर्श से करता है।
- D) उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राज्यपाल को सौंपता है।

प्रश्न 21:

कथन I : अनुच्छेद 170 के तहत राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 200 निर्धारित है, जिनमें अनुसूचित जाति (SC) के लिए 34 और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए 25 सीटें आरक्षित हैं।

कथन II: विधानसभा की बैठक के लिए कुल सदस्य संख्या का 1/5वां भाग (40 सदस्य) गणपूर्ति (कोरम) के रूप में अनिवार्य रूप से उपस्थित होना चाहिए।

कथन III: विधानसभा का कार्यकाल अपनी पहली बैठक के लिए तय तिथि से 5 वर्ष होता है, और राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद एक बार में कार्यकाल 2 वर्ष तक बढ़ा सकती है।

उपरोक्त में से कौनसा/कौनसे कथन/कथन समूह सत्य है :

- A) केवल 1
- B) केवल 1 और 2
- C) केवल 2 और 3
- D) केवल 1 और 3

प्रश्न 22:

कथन: 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से राज्य मंत्रिपरिषद के आकार को मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15 प्रतिशत तक सीमित किया गया है, तथा न्यूनतम संख्या 12 निर्धारित है।

कारण: अति-आकार के मंत्रिमंडल और दल-बदल संस्कृति पर राजकोषीय व प्रशासनिक दबाव कम करने के उद्देश्य से संसद ने यह प्रतिबंधात्मक प्रावधान संविधान के भाग 6 में जोड़े।

- A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या करता है
- B) A और R दोनों सत्य हैं परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं करता है
- C) A सत्य है परंतु R असत्य है
- D) A असत्य है परंतु R सत्य है

प्रश्न 23:

कथन: मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का केंद्रक और राज्य प्रशासन का वास्तविक धुरी होता है, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है।

निष्कर्ष I : मुख्यमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र से पूरी मंत्रिपरिषद स्वतः विघटित हो जाती है।

निष्कर्ष II : यदि कोई गैर-सदस्य मुख्यमंत्री नियुक्त होता है, तो उसे 1 वर्ष के भीतर विधानमंडल की सदस्यता प्राप्त करना अनिवार्य है।

- A) केवल निष्कर्ष I सत्य है
- B) केवल निष्कर्ष II सत्य है
- C) निष्कर्ष I और II दोनों असत्य हैं
- D) केवल I व II का तार्किक संमिश्रण

प्रश्न 24:सुमेलित कीजिये

सूची I : राजस्थान विधान सभाओं के विशिष्ट कालखंड / नेतृत्व

- a) प्रथम विधानसभा (1952-1957)
- b) चतुर्थ विधानसभा (1967-1972)
- c) छठी विधानसभा (1977-1980)
- d) समकालीन चक्रीय क्रम रुझान

सूची II : राजनीतिक/प्रशासनिक विशेषता

I) प्रथम गैर-कांग्रेस जनता पार्टी सरकार और ग्रामीण भागीदारी

II) प्रथम राष्ट्रपति शासन एवं दलीय विखंडन का दौर

III) सामंती ढांचे से लोकतांत्रिक संसदीय तंत्र में संक्रमण

IV) प्रत्येक 5 वर्ष पर सत्ता परिवर्तन का चक्रीय क्रम

- A) a-III, b-II, c-I, d-IV
- B) a-I, b-II, c-III, d-IV
- C) a-IV, b-III, c-II, d-I
- D) a-II, b-I, c-IV, d-III

प्रश्न 25:

असंगत कथन की पहचान करें :

- A) 10वीं अनुसूची के तहत दलबदल के आधार पर अयोग्यता का निर्णय विधान सभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है।
- B) कीहोटो होलोहोन वाद (1992) में न्यायालय ने माना कि अध्यक्ष का दलबदल संबंधी निर्णय न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन है।
- C) मूल दल के एक-तिहाई सदस्यों के विलय पर दलबदल कानून लागू नहीं होता है।
- D) कीशम मेघचंद्र सिंह वाद (2020) में अध्यक्ष को 3 महीने के भीतर निर्णय लेने की संस्तुति दी गई।

प्रश्न 26:

आधुनिक संसदीय समितियों और दलबदल/विशेषाधिकार तंत्र के बीच, लोक लेखा समिति (PAC) विपक्ष के नेतृत्व की स्वस्थ परंपरा के साथ कैग रिपोर्ट की संवीक्षा करती है, जबकि अनुच्छेद 194 सदस्यों को सदन के भीतर वाक-स्वाधीनता देता है।

उपरोक्त परिच्छेद के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक तार्किक निष्कर्ष है?

- A) PAC नीति की बुद्धिमत्ता की समीक्षा करती है।
- B) PAC का सभापति पारंपरिक रूप से विपक्ष दल से नियुक्त किया जाता है जो वित्तीय जवाबदेही पुष्ट करता है।
- C) अनुच्छेद 194 के तहत आपराधिक मामलों में भी सदन सत्र दौरान पूर्ण गिरफ्तारी मुक्ति मिलती है।

D) प्राक्कलन समिति भूतकालीन व्यय की CAG रिपोर्ट जाँचती है।

प्रश्न 27:

कथन I : विधान सभा अध्यक्ष धन विधेयक (Money Bill) होने या न होने का अंतिम निर्णय देता है (अनुच्छेद 199)।

कथन II: अध्यक्ष प्रथम दृष्टया मत देता है, किंतु मतों की समानता (Tie) पर उसका निर्णायक मत (Casting Vote) नहीं होता।

कथन III: उपाध्यक्ष अध्यक्ष की अनुपस्थिति में समस्त अध्यक्षीय शक्तियों का प्रयोग करता है। उपरोक्त में से कौनसा/कौनसे कथन/कथन समूह सत्य है :

- A) केवल 1 और 2
- B) केवल 2 और 3
- C) केवल 1 और 3
- D) केवल 1

प्रश्न 28:

कथन: अनुच्छेद 194(3) के तहत राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के समतुल्य माने गए थे जिन्हें 44वें संशोधन 1978 से संशोधित किया गया।

कारण: केशवानंद भारती वाद (1973) ने विशेषाधिकारों को मूल अधिकारों से ऊपर सर्वोपरि स्थान दिया।

- A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या करता है
- B) A और R दोनों सत्य हैं परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं करता है
- C) A सत्य है परंतु R असत्य है
- D) A असत्य है परंतु R सत्य है

प्रश्न 29:

कथन: मंत्रिमंडलीय समितियाँ संविधानेतर किंतु प्रशासनिक दृष्टि से अनिवार्य कार्यकारी निकाय हैं।

निष्कर्ष I : मुख्यमंत्री अधिकांश मंत्रिमंडलीय समितियों के अध्यक्ष होते हैं।

निष्कर्ष II : मंत्रिमंडलीय समितियों के निर्णयों को कैबिनेट द्वारा बाद में संपुष्टि (Ratification) की आवश्यकता नहीं होती।

- A) केवल निष्कर्ष I सत्य है
- B) केवल निष्कर्ष II सत्य है

- C) निष्कर्ष I और II दोनों असत्य हैं
- D) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 30:सुमेलित कीजिये

सूची I : वित्तीय एवं विधायी समितियाँ

- a) लोक लेखा समिति (PAC)
- b) प्राक्कलन समिति 'अ' एवं 'ब'
- c) सार्वजनिक उपक्रम समिति
- d) प्रत्यायोजित विधान समिति

सूची II : संरचना / मुख्य कार्य

- I) बजट अनुमानों में मितव्ययिता परीक्षण (15x2 सदस्य)
- II) कैग रिपोर्ट एवं विनियोग लेखा संवीक्षा (15 सदस्य, विपक्ष सभापति)
- III) कार्यपालिका द्वारा बनाए गए नियमों की अत्यधिक प्रत्यायोजन जाँच
- IV) राज्य निगमों/उपक्रमों के वाणिज्यिक निष्पादन की समीक्षा
- A) a-II, b-I, c-IV, d-III
- B) a-I, b-II, c-III, d-IV
- C) a-IV, b-III, c-II, d-I
- D) a-III, b-IV, c-I, d-II

प्रश्न 31:

असंगत कथन की पहचान करें :

- A) हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे (1949)।
- B) मोहनलाल सुखाड़िया का कार्यकाल लगभग 17 वर्ष रहा जो सर्वाधिक है।
- C) बरकत उल्ला खान प्रदेश के प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री थे।
- D) भैरोसिंह शेखावत प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अंत्योदय योजना चलाई।

प्रश्न 32:

कथन: 16वीं विधानसभा (2023) चुनाव उपरांत भजनलाल शर्मा ने नेतृत्व संभाला और ईआरसीपी जैसे जल समझौते प्रमुख बिंदु रहे।

निष्कर्ष I : राजस्थान में पिछले दो दशकों से प्रत्येक 5 वर्ष पर सत्ता परिवर्तन का चक्रीय रुझान रहा है।

निष्कर्ष II : 16वीं विधानसभा में कांग्रेस को 115 से अधिक सीटें मिलीं।

- A) केवल निष्कर्ष I सत्य है
- B) केवल निष्कर्ष II सत्य है

- C) निष्कर्ष I और II दोनों असत्य हैं
D) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 33:

कथन I : अनुच्छेद 167 के तहत मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वह प्रशासन एवं विधान विषयक प्रस्तावों की सूचना राज्यपाल को दे।

कथन II: यदि किसी मंत्री ने विनिश्चय किया है और मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया, तो राज्यपाल अपेक्षा कर सकता है।

कथन III: मुख्यमंत्री राज्यपाल की सलाह के बिना किसी भी मंत्री को कभी हटा नहीं सकता।
उपरोक्त में से कौनसा/कौनसे कथन/कथन समूह सत्य है :

- A) केवल 1 और 2
B) केवल 2 और 3
C) केवल 1 और 3
D) केवल 1

प्रश्न 34:

कथन: केश सिंह वाद (1965) में विधान सभा ने विशेषाधिकार हनन पर कारावास दिया और उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने पर न्यायालय को नोटिस दिया।

कारण: उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि विधान सभा के विशेषाधिकार मूल अधिकारों या जीवन/स्वतंत्रता के उल्लंघन के संदर्भ में न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर हैं।

- A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या करता है
B) A और R दोनों सत्य हैं परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं करता है
C) A सत्य है परंतु R असत्य है
D) A असत्य है परंतु R सत्य है

प्रश्न 35:

असंगत कथन की पहचान करें :

- A) अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा की अधिकतम संख्या 500 हो सकती है।
B) राजस्थान विधानसभा में अनुसूचित जनजाति की 25 सीटें आरक्षित हैं।
C) प्रो-टेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
D) विधान सभा की बैठक के लिए गणपूर्ति 20 सदस्य (1/10वां भाग) है।

प्रश्न 36:

कथन: राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA) के माध्यम से विधान सभाओं को पेपरलेस कार्यप्रणाली की ओर ले जाया जा रहा है।

निष्कर्ष I : NeVA से कागजी अपव्यय कम हुआ है और साक्ष्यों/प्रश्नों की डिजिटल ट्रैकिंग पारदर्शी हुई है।

निष्कर्ष II : NeVA लागू होने के बाद सदन में मौखिक प्रश्न पूछने पर प्रतिबंध लग गया है।

- A) केवल निष्कर्ष I सत्य है
B) केवल निष्कर्ष II सत्य है
C) निष्कर्ष I और II दोनों असत्य हैं
D) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 37:

कथन I : 91वें संशोधन 2003 के अनुसार मंत्री संख्या विधानसभा कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी।

कथन II: छोटे राज्यों के लिए न्यूनतम मंत्री संख्या 12 का अपवाद/प्रावधान है।

कथन III: दलबदल के आधार पर अयोग्य ठहराया गया व्यक्ति मंत्री पद के लिए पात्र बना रहता है।
उपरोक्त में से कौनसा/कौनसे कथन/कथन समूह सत्य है :

- A) केवल 1 और 2
B) केवल 2 और 3
C) केवल 1 और 3
D) केवल 1

प्रश्न 38:

कथन: सर्वलाइट वाद (1959) में उच्चतम न्यायालय ने वाक-स्वाधीनता और विशेषाधिकार संघर्ष पर निर्णय दिया।

कारण: अनुच्छेद 194(3) के विशेषाधिकारों को विशिष्ट मामलों में प्राथमिकता दी गई थी।

- A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या करता है
B) A और R दोनों सत्य हैं परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं करता है
C) A सत्य है परंतु R असत्य है
D) A असत्य है परंतु R सत्य है

प्रश्न 39:

असंगत कथन की पहचान करें :

- A) अनुच्छेद 189 के अनुसार मतों की समानता पर पीठासीन अधिकारी का कास्टिंग वोट होता है।
- B) राजस्थान विधानसभा में वर्तमान में 200 निर्वाचित सदस्य हैं।
- C) विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र मुख्यमंत्री को सौंपता है।
- D) उपाध्यक्ष का निर्वाचन विधानसभा अपने सदस्यों में से करती है।

प्रश्न 40:

कथन: बहु-पक्षीय गठबंधन और क्षेत्रीय दलों (जैसे BAP) का उभार राजस्थान की पारंपरिक द्वि-ध्रुवीय राजनीति को सूक्ष्म बना रहा है।

निष्कर्ष I : भारत आदिवासी पार्टी का प्रभाव मुख्य रूप से आदिवासी बहुल दक्षिणी क्षेत्रों में है।

निष्कर्ष II : क्षेत्रीय दल द्वि-ध्रुवीय संतुलन को पूरी तरह समाप्त कर चुके हैं।

- A) केवल निष्कर्ष I सत्य है
- B) केवल निष्कर्ष II सत्य है
- C) निष्कर्ष I और II दोनों असत्य हैं
- D) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 41:

कथन I : अनुच्छेद 315 के अनुसार संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा।

कथन II: राज्य लोक सेवा आयोग के आधे सदस्यों के पास कम से कम 10 वर्ष का भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन न्यायिक पद का अनुभव होना चाहिए।

कथन III: राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वे 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं।

उपरोक्त में से कौनसा/कौनसे कथन/कथन समूह सत्य है :

- A) केवल 1 और 2
- B) केवल 1 और 3
- C) केवल 2 और 3
- D) केवल 1

प्रश्न 42:

कथन: राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर केवल राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है, राज्यपाल द्वारा नहीं।

कारण: राष्ट्रपति को ऐसा करने से पहले मामले को उच्चतम न्यायालय को जांच के लिए भेजना अनिवार्य होता है और उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट बाध्यकारी होती है।

- A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या करता है
- B) A और R दोनों सत्य हैं परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं करता है
- C) A सत्य है परंतु R असत्य है
- D) A असत्य है परंतु R सत्य है

प्रश्न 43:

कथन: लोक सेवा आयोग का कार्य सिविल सेवा भर्ती और अनुशासनात्मक परामर्श देना है, किंतु आरक्षण के प्रतिशत तय करना इसका अनिवार्य क्षेत्राधिकार नहीं है।

निष्कर्ष I : राज्य सरकार आरक्षण तय करते समय RPSC से सलाह लेने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य है।

निष्कर्ष II : RPSC का वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है जो विधानमंडल के पटल पर रखा जाता है।

- A) केवल निष्कर्ष I सत्य है
- B) केवल निष्कर्ष II सत्य है
- C) निष्कर्ष I और II दोनों असत्य हैं
- D) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 44:सुमेलित कीजिये

सूची I : संवैधानिक एवं सांविधिक अभिकरण

- a) राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC)
- b) राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRC)
- c) राज्य निर्वाचन आयोग (SEC)
- d) राज्य सूचना आयोग (SIC)

सूची II : स्थापना/गठन वर्ष या प्रमुख मुख्यालय आधार

- I) अजमेर मुख्यालय, 20 अगस्त 1949 स्थापना
 - II) जयपुर मुख्यालय, 18 जनवरी 1999 गठन
 - III) जयपुर मुख्यालय, दिसंबर 1994 गठन
 - IV) जयपुर मुख्यालय, 13 अप्रैल 2006 गठन
- A) a-II, b-I, c-IV, d-III

- B) a-I, b-II, c-III, d-IV
C) a-IV, b-III, c-II, d-I
D) a-III, b-IV, c-I, d-II

प्रश्न 45:

असंगत कथन की पहचान करें :

- A) RPSC के प्रथम अध्यक्ष एस.के. घोष थे।
B) RPSC सदस्यों की सेवा शर्तों में नियुक्ति के पश्चात लाभकारी परिवर्तन किए जा सकते हैं।
C) RPSC के व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं।
D) आयोग का अध्यक्ष अपने उसी पद पर पुनर्नियुक्त नहीं हो सकता।

प्रश्न 46:

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत पेरिस सिद्धांतों की अनुपालना में SHRC का गठन किया जाता है, जहाँ 2019 संशोधन ने पदावधि 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दी है।
उपरोक्त परिच्छेद के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है?

- A) SHRC अध्यक्ष के रूप में केवल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ही बैठ सकते हैं।
B) 2019 संशोधन के बाद पदावधि 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) हो गई है।
C) SHRC के अध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है।
D) SHRC के पास सिविल न्यायालय की कोई शक्ति नहीं होती है।

प्रश्न 47:

कथन I : मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा SHRC का गठन करती है।

कथन II: 2019 संशोधन के पश्चात राजस्थान मानवाधिकार आयोग में 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं।

कथन III: SHRC के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति की संस्तुति पर होती है।
उपरोक्त में से कौनसा/कौनसे कथन/कथन समूह सत्य है :

- A) केवल 1 और 3
B) केवल 2 और 3
C) केवल 1 और 2
D) केवल 3

प्रश्न 48:

कथन: राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रकृति मुख्य रूप से सलाहकारी और अनुशासनात्मक संस्तुति वाली है।

कारण: आयोग के पास सीधे तौर पर किसी दोषी लोक सेवक को जेल भेजने या स्वयं प्रतिकर राशि वसूलने का दंडात्मक अधिकार नहीं है।

- A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या करता है
B) A और R दोनों सत्य हैं परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं करता है
C) A सत्य है परंतु R असत्य है
D) A असत्य है परंतु R सत्य है

प्रश्न 49:

कथन: SHRC चयन समिति में विधान सभा के अध्यक्ष और विपक्ष के नेता शामिल होते हैं।

निष्कर्ष I : मुख्यमंत्री इस चयन समिति के अध्यक्ष होते हैं।

निष्कर्ष II : एकसदनीय विधानसभा होने पर विधान परिषद के सदस्यों का कोई स्थान नहीं होता।

- A) केवल निष्कर्ष I सत्य है
B) केवल निष्कर्ष II सत्य है
C) निष्कर्ष I और II दोनों सत्य हैं
D) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 50:सुमेलित कीजिये

सूची I : मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष (राजस्थान)

- a) न्यायमूर्ति कांता भटनागर
b) न्यायमूर्ति सगेर अहमद
c) न्यायमूर्ति प्रकाश टाटिया
d) मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम धारा 12

सूची II : मुख्य वैधानिक/संस्थागत संदर्भ

- I) आयोग के मुख्य कृत्य व स्वतः संज्ञान जाँच अधिकार
II) प्रथम अध्यक्ष, राजस्थान मानवाधिकार आयोग
III) सर्वोच्च न्यायालय पूर्व न्यायाधीश, अध्यक्ष कार्यकाल
IV) उच्च न्यायालय पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति, अध्यक्ष कार्यकाल
A) a-II, b-III, c-IV, d-I

- B) a-I, b-II, c-III, d-IV
C) a-IV, b-I, c-II, d-III
D) a-III, b-IV, c-I, d-II

प्रश्न 51:

असंगत कथन की पहचान करें :

- A) राजस्थान लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त अधिनियम 1973 में प्रवृत्त हुआ।
B) लोकायुक्त का कार्यकाल प्रारंभिक रूप से 5 वर्ष था और पुनर्नियुक्ति निषेध है।
C) मुख्यमंत्री को राजस्थान लोकायुक्त के प्रत्यक्ष अन्वेषण दायरे से बाहर रखा गया है।
D) लोकायुक्त का वार्षिक प्रतिवेदन सीधे राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है।

प्रश्न 52:

कथन: लोकायुक्त प्रशासनिक कदाचार और भ्रष्टाचार की स्वतंत्र जांच करता है।

कारण: RPSC अध्यक्ष और सदस्य लोकायुक्त के दायरे से बाहर रखे गए हैं क्योंकि उनकी पदमुक्ति अनुच्छेद 317 के तहत होती है।

- A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या करता है
B) A और R दोनों सत्य हैं परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं करता है
C) A सत्य है परंतु R असत्य है
D) A असत्य है परंतु R सत्य है

प्रश्न 53:

कथन I : लोकायुक्त लोकायुक्त अधिनियम 1973 के तहत मंत्रियों और लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच कर सकता है।

कथन II: उच्च न्यायालय के न्यायाधीश लोकायुक्त के दायरे में आते हैं।

कथन III: 5 वर्ष से पुराने मामले सामान्यतः लोकायुक्त के दायरे से बाहर माने जाते हैं।
उपरोक्त में से कौनसा/कौनसे कथन/कथन समूह सत्य है :

- A) केवल 1 और 3
B) केवल 2 और 3
C) केवल 1 और 2
D) केवल 1

प्रश्न 54:

असंगत कथन की पहचान करें :

- A) अनुच्छेद 243-K पंचायतों के निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है।
B) राज्य निर्वाचन आयुक्त को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान हटाया जाता है।
C) राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
D) राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग दिसंबर 1994 में गठित हुआ।

प्रश्न 55:

स्थानीय निकाय चुनावों में राज्य निर्वाचन आयोग मतदाता सूचियों से लेकर आचार संहिता लागू करने और ईवीएम/बैलेट प्रबंधन तक सब देखता है।
उपरोक्त परिच्छेद के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है?

- A) राज्य निर्वाचन आयोग संसद सदस्य के भी चुनाव कराता है।
B) आदर्श आचार संहिता स्थानीय चुनाव के दौरान SEC द्वारा प्रभावी की जाती है।
C) वार्डों का परिसीमन पूरी तरह SEC का स्वतंत्र अधिकार है जिसमें राज्य सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती।
D) प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त अमर सिंह राठौड़ नहीं थे।

प्रश्न 56:

कथन I : सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सामान्य सूचना 30 दिनों में देनी होती है।

कथन II: जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में सूचना 48 घंटों में देनी होती है।

कथन III: राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के साथ अधिकतम 50 आयुक्त हो सकते हैं।

उपरोक्त में से कौनसा/कौनसे कथन/कथन समूह सत्य है :

- A) केवल 1 और 2
B) केवल 2 और 3
C) केवल 1 और 3
D) केवल 1

प्रश्न 57:

कथन: जन सूचना अधिकारी द्वारा बिना उचित कारण विलंब करने पर ₹250 प्रति दिन और अधिकतम ₹25,000 की शास्ति (Penalty) धारा 20 के तहत लगाई जा सकती है।

कारण: राज्य सूचना आयोग अर्द्ध-न्यायिक निकाय के रूप में अनुशासनात्मक कार्यवाई की भी संस्तुति कर सकता है।

- A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या करता है
B) A और R दोनों सत्य हैं परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं करता है
C) A सत्य है परंतु R असत्य है
D) A असत्य है परंतु R सत्य है

प्रश्न 58:

असंगत कथन की पहचान करें :

- A) प्रथम अपीलीय प्राधिकारी विभागीय वरिष्ठ अधिकारी होता है।
B) द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग के समक्ष 90 दिनों के भीतर होती है।
C) इंटेलीजेंस ब्यूरो (IB) पूरी तरह आरटीआई अधिनियम के दायरे में आती है।
D) राजस्थान राज्य सूचना आयोग 13 अप्रैल 2006 को गठित हुआ।

प्रश्न 59:सुमेलित कीजिये

सूची I : वैधानिक प्रावधान / धारा संदर्भ

- a) RTI धारा 2(f)
b) RTI धारा 4
c) RTI धारा 8
d) RTI धारा 24

सूची II : विषय-वस्तु

- I) सूचना की परिभाषा
II) स्व-प्रेरित (proactive) प्रकटीकरण दायित्व
III) सूचना से छूट (राष्ट्रीय सुरक्षा आदि)
IV) गुप्तचर/सुरक्षा संगठनों को छूट
A) a-I, b-II, c-III, d-IV
B) a-IV, b-III, c-II, d-I
C) a-II, b-I, c-IV, d-III
D) a-III, b-IV, c-I, d-II

प्रश्न 60:

कथन: SVEEP मॉडल और डिजिटल ई-वोटर स्लिप स्थानीय निकायों में मतदान प्रतिशत और पारदर्शिता बढ़ाते हैं।

निष्कर्ष I : राज्य निर्वाचन आयोग स्थानीय चुनावों में डिजिटल नॉमिनेशन पोर्टल का उपयोग कर रहा है।

निष्कर्ष II : दिव्यांगजनों के लिए पीडब्ल्यूडी मोबाइल ऐप स्थानीय चुनावों में अप्रयोज्य है।

- A) केवल निष्कर्ष I सत्य है
B) केवल निष्कर्ष II सत्य है
C) निष्कर्ष I और II दोनों असत्य हैं
D) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 61:

कथन I : राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी गांव में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था।

कथन II: संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान नीति-निर्देशक तत्वों के रूप में शामिल है।

कथन III: 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में भाग 9 और बारहवीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 29 विषय हैं। उपरोक्त में से कौनसा/कौनसे कथन/कथन समूह सत्य है :

- A) केवल 1 और 2
B) केवल 2 और 3
C) केवल 1 और 3
D) केवल 1

प्रश्न 62:

कथन: 73वें संविधान संशोधन के तहत ग्राम सभा को ग्रामीण लोकतंत्र की मूल सभा और सामाजिक अंकेक्षण का अधिकार दिया गया है।

कारण: संविधान का अनुच्छेद 243-G ग्यारहवीं अनुसूची के 29 विषयों पर पंचायतों को योजना निर्माण और कार्यान्वयन की शक्ति प्रदान करता है।

- A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या करता है
B) A और R दोनों सत्य हैं परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं करता है
C) A सत्य है परंतु R असत्य है
D) A असत्य है परंतु R सत्य है

प्रश्न 63:

कथन: त्रि-स्तरीय पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद संरचनात्मक इकाइयां हैं।

निष्कर्ष I : जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है, वे मध्यवर्ती ब्लॉक स्तर का गठन करने के लिए बाध्य नहीं हैं।

निष्कर्ष II : पंचायत समिति के राजनीतिक प्रमुख सरपंच होते हैं।

- A) केवल निष्कर्ष I सत्य है
- B) केवल निष्कर्ष II सत्य है
- C) निष्कर्ष I और II दोनों असत्य हैं
- D) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 64: सुमेलित कीजिये

सूची I : पंचायती राज / स्थानीय स्वशासन संदर्भ

- a) 73वां संविधान संशोधन
- b) 74वां संविधान संशोधन
- c) बलवंत राय मेहता समिति
- d) एल.एम. सिंघवी समिति

सूची II : मुख्य आयाम / वर्ष

- I) 1986 में संवैधानिक दर्जा देने की प्रथम संस्तुति
- II) 1957 की त्रि-स्तरीय विकेंद्रीकरण संस्तुति
- III) 24 अप्रैल 1993 से प्रवृत्त (भाग 9, 29 विषय)
- IV) 1 जून 1993 से प्रवृत्त (भाग 9-क, 18 विषय)
- A) a-III, b-IV, c-II, d-I
- B) a-I, b-II, c-III, d-IV
- C) a-IV, b-III, c-II, d-I
- D) a-III, b-I, c-IV, d-II

प्रश्न 65:

असंगत कथन की पहचान करें :

- A) राज्य सचिवालय राज्य प्रशासन का बौद्धिक थिंक-तंक कहलाता है।
- B) मुख्य सचिव का पद संविधान के अनुच्छेद 167 में विशिष्ट रूप से परिभाषित है।
- C) सचिवालय एक स्टाफ एजेंसी है जबकि निदेशालय लाइन एजेंसी है।
- D) अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव विभाग के प्रशासनिक प्रभारी होते हैं।

प्रश्न 66:

मुख्य सचिव राज्य प्रशासन का सर्वोच्च सिविल सेवक और मंत्रिमंडल का सचिव होता है जो अंतर-विभागीय समन्वय और संकट प्रबंधन की सर्वोच्च कमान संभालता है। उपरोक्त परिच्छेद के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है?

- A) मुख्य सचिव की नियुक्ति सीधे राज्यपाल अपने स्वविवेक से बिना मुख्यमंत्री परामर्श के करता है।
- B) मुख्य सचिव मंत्रिमंडल की बैठकों का एजेंडा तैयार करता है और निर्णयों की अनुपालना कराता है।
- C) मुख्य सचिव सचिवालय का अनुभाग अधिकारी (SO) स्तर का निचला पद है।
- D) मुख्य सचिव राज्य पुलिस महानिदेशक के अधीनस्थ कार्य करता है।

प्रश्न 67:

कथन I : राज्य सचिवालय नीति-निर्माण और विधायी ड्राफ्टिंग का केंद्र है।

कथन II: निदेशालय मैदानी योजनाओं के क्रियान्वयन और पर्यवेक्षण का कार्य करता है।

कथन III: सचिवालय भवन को लाइन एजेंसी कहा जाता है। उपरोक्त में से कौनसा/कौनसे कथन/कथन समूह सत्य है :

- A) केवल 1 और 2
- B) केवल 2 और 3
- C) केवल 1 और 3
- D) केवल 1

प्रश्न 68:

कथन: 74वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9-क और बारहवीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 18 शहरी विषय विनिर्दिष्ट हैं।

कारण: बारहवीं अनुसूची में केवल ग्रामीण स्वच्छता और पशुपालन के विषय शामिल किए गए हैं।

- A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या करता है
- B) A और R दोनों सत्य हैं परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं करता है
- C) A सत्य है परंतु R असत्य है
- D) A असत्य है परंतु R सत्य है

प्रश्न 69:

कथन: राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 राज्य के सभी नगरीय निकायों का शासी कानून है।

निष्कर्ष I : नगर निगम के राजनीतिक प्रमुख महापौर होते हैं और प्रशासनिक प्रमुख आयुक्त होते हैं।

निष्कर्ष II : नगरपालिका के प्रशासनिक प्रमुख को सीईओ (CEO) कहा जाता है जो IAS होता है।

- A) केवल निष्कर्ष I सत्य है
- B) केवल निष्कर्ष II सत्य है
- C) निष्कर्ष I और II दोनों असत्य हैं
- D) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 70: सुमेलित कीजिये

सूची I : नगरीय निकाय / प्राधिकारी

- a) नगर निगम
- b) नगर परिषद
- c) नगरपालिका
- d) वार्ड समिति

सूची II : मानक/प्रावधान पैमाना

- I) 3 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले निकाय क्षेत्रों में गठन
- II) वृहद महानगर / उच्च जनसंख्या क्षेत्र (आयुक्त IAS/RAS)
- III) मध्यम आकार के शहर / जिला मुख्यालय (आयुक्त RAS)
- IV) छोटे नगर या संक्रमणकालीन क्षेत्र (अधिशाली अधिकारी EO)
- A) a-II, b-III, c-IV, d-I
- B) a-I, b-II, c-III, d-IV
- C) a-IV, b-III, c-II, d-I
- D) a-III, b-IV, c-I, d-II

प्रश्न 71:

असंगत कथन की पहचान करें :

- A) जिला कलेक्टर लार्ड कोर्नवॉलिस के काल में राजस्व और न्यायिक समन्वय हेतु सृजित हुआ था।
- B) जिला कलेक्टर भारतीय दंड संहिता की धारा 144 जैसे निषेधाज्ञा आदेश DM के रूप में जारी करता है।
- C) उप-खंड अधिकारी (SDO) उप-खंड स्तर पर राजस्व अपील और मजिस्ट्रेटियल नियंत्रण करता है।
- D) पटवारी ग्राम स्तर का भू-राजस्व संग्रहण प्रमुख होता है जिसे तहसील का संपूर्ण वित्तीय अधिकार होता है।

प्रश्न 72:

कथन: जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) का पदेन अध्यक्ष जिला कलेक्टर होता है।

कारण: आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत DDMA आपदा योजना और राहत समन्वय करता है।

- A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या करता है
- B) A और R दोनों सत्य हैं परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं करता है
- C) A सत्य है परंतु R असत्य है
- D) A असत्य है परंतु R सत्य है

प्रश्न 73:

कथन I : जिला स्तर पर शांति-व्यवस्था की दोहरी धुरी कलेक्टर (DM) और पुलिस अधीक्षक (SP) हैं।

कथन II: दंडात्मक और निषेधात्मक शक्तियों का अंतिम वैधानिक प्राधिकार जिला दंडाधिकारी के पास होता है।

कथन III: पुलिस अधीक्षक बल का deployment और अन्वेषण नियंत्रण रखता है।

उपरोक्त में से कौनसा/कौनसे कथन/कथन समूह सत्य है :

- A) केवल 1 और 2
- B) केवल 2 और 3
- C) केवल 1 और 3
- D) केवल 1

प्रश्न 74:

असंगत कथन की पहचान करें :

- A) राजस्थान पुलिस बल पर वैधानिक नियंत्रण पुलिस अधिनियम 1861 से संचालित होता है।
- B) पुलिस महानिदेशक (DGP) राज्य पुलिस बल का सर्वोच्च ऑपरेशनल मुखिया होता है।
- C) जयपुर और जोधपुर महानगरों में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू है।
- D) पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली में कमिश्नर रैंक का अधिकारी जिले का डीएन/एसपी नहीं बल्कि उच्च रैंक रखता है और DM के अधीन होता है।

प्रश्न 75:

कथन: प्रकाश सिंह वाद (2006) में सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस सुधार हेतु डीजीपी का निश्चित कार्यकाल और पुलिस स्थापना बोर्ड जैसे निर्देश दिए।

निष्कर्ष I : पुलिस स्थापना बोर्ड स्थानांतरण और पदस्थापन में राजनीतिक हस्तक्षेप समाप्त करने में सहायक है।

निष्कर्ष II : प्रकाश सिंह वाद के निर्देश केवल राजस्थान पर लागू हैं, अन्य राज्यों पर नहीं।

- A) केवल निष्कर्ष I सत्य है
- B) केवल निष्कर्ष II सत्य है
- C) निष्कर्ष I और II दोनों असत्य हैं
- D) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 76: सुमेलित कीजिये

सूची I : पुलिस इकाइयां / मॉडल

- a) सीआईडी-सीबी (CID-CB)
- b) एसजी / एसओजी (SOG)
- c) साइबर क्राइम सेल
- d) सुरक्षा सखी

सूची II : मुख्य कार्यक्षेत्र

- I) गंभीर एवं सनसनीखेज मामलों का विशेष अन्वेषण
 - II) संगठित अपराध, माफिया व प्रतियोगी परीक्षा शुचिता भंग गिरोह जाँच
 - III) वित्तीय फ्रॉड/गोल्डन ऑवर राशि फ्रीज (1930 NCRP समन्वय)
 - IV) महिला/बाल सुरक्षा हेतु सामुदायिक वालंटियर नेटवर्क
- A) a-I, b-II, c-III, d-IV
 - B) a-II, b-I, c-IV, d-III
 - C) a-IV, b-III, c-II, d-I
 - D) a-III, b-IV, c-I, d-II

प्रश्न 77:

असंगत कथन की पहचान करें :

- A) ग्राम पंचायत का राजनीतिक प्रमुख सरपंच होता है जो सीधे निर्वाचित होता है।
- B) पंचायत समिति का प्रशासनिक प्रमुख विकास अधिकारी (BDO) होता है।
- C) जिला परिषद का प्रशासनिक प्रमुख मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) होता है।
- D) पंचायत समिति के प्रधान का निर्वाचन वार्ड सदस्यों द्वारा नहीं बल्कि ग्राम सभा के सभी मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष होता है।

प्रश्न 78:

कथन I : राज्य वित्त आयोग राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर गठित किया जाता है (अनुच्छेद 243-I/243-Y)।

कथन II : राज्य वित्त आयोग पंचायतों और नगरपालिकाओं के बीच करों के देवोल्यूशन के सिद्धांत तय करता है।

कथन III : राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियां सरकार के लिए पूर्णतः बाध्यकारी होती हैं।

उपरोक्त में से कौनसा/कौनसे कथन/कथन समूह सत्य है :

- A) केवल 1 और 2
- B) केवल 2 और 3
- C) केवल 1 और 3
- D) केवल 1

प्रश्न 79:

कथन: राजस्थान में लोकायुक्त संस्था 1973 अधिनियम से संचालित है, जबकि ई-गवर्नेंस पहले पारदर्शी सेवा देती हैं।

निष्कर्ष I : स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किए गए हैं।

निष्कर्ष II : ई-मित्र प्लस मानवरहित टचस्क्रीन कियोस्क 24x7 सेवा देते हैं।

- A) केवल निष्कर्ष I सत्य है
- B) केवल निष्कर्ष II सत्य है
- C) निष्कर्ष I और II दोनों असत्य हैं
- D) निष्कर्ष I और II दोनों सत्य हैं

प्रश्न 80:

संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में 29 कार्यकारी विषय हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म/विषय पंचायती राज के 29 विषयों से संबंधित नहीं है?

- A) कृषि और भूमि सुधार
- B) प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा
- C) रक्षा एवं परमाणु ऊर्जा नीति
- D) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) पर्यवेक्षण

प्रश्न 81:

कथन I : राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के तहत चिन्हित सेवाओं में विलंब करने पर पदांकित अधिकारी पर शास्ति लगाई जा सकती है।

कथन II : राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 के तहत जनसुनवाई अधिकारी (PHO) परिवार का समयबद्ध निस्तारण करता है।

कथन III: सिटिजन चार्टर का मूल दर्शन प्रशासन को 'प्रजा-केंद्रित' बनाना है।

उपरोक्त में से कौनसा/कौनसे कथन/कथन समूह सत्य है :

- A) केवल 1 और 2
- B) केवल 2 और 3
- C) केवल 1 और 3
- D) केवल 1

प्रश्न 82:

कथन: सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) मनरेगा की धारा 17 के तहत ग्राम सभा द्वारा सहभागी और धरातलीय सत्यापन की प्रक्रिया है।

कारण: सामाजिक अंकेक्षण का मुख्य फोकस केवल कागजी वाउचरों की गणितीय और अर्थमितीय शुद्धता का मिलान करना होता है।

- A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या करता है
- B) A और R दोनों सत्य हैं परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं करता है
- C) A सत्य है परंतु R असत्य है
- D) A असत्य है परंतु R सत्य है

प्रश्न 83:

कथन: POSH Act 2013 के तहत 10 या अधिक कर्मचारियों वाले कार्यालयों में आंतरिक शिकायत समिति (ICC) का गठन अनिवार्य है।

निष्कर्ष I : ICC की पीठासीन अधिकारी संगठन की उच्च स्तर की महिला होनी चाहिए।

निष्कर्ष II : POCSO Act 2012 लिंग-तटस्थ कानून नहीं है क्योंकि यह केवल बालिकाओं पर लागू होता है।

- A) केवल निष्कर्ष I सत्य है
- B) केवल निष्कर्ष II सत्य है
- C) निष्कर्ष I और II दोनों असत्य हैं
- D) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 84:सुमेलित कीजिये

सूची I : ई-गवर्नेंस एवं सुशासन पहलें

- a) ई-मित्र (e-Mitra)
- b) राजस्थान संपर्क
- c) जन आधार
- d) iStart राजस्थान

सूची II : मुख्य आयाम / उद्देश्य

I) एकल परिवार पहचान संख्या एवं डीबीटी लाभार्थ आधार

II) कियोस्क नेटवर्क के जरिए G2C/B2C डिजिटल सेवाएं

III) 181 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन एवं सिंगल-विंडो ग्रीवांस रिड्रेसल

IV) स्टार्टअप्स, इन्क्यूबेशन हब और इनोवेशन चैलेंज फंड

A) a-II, b-III, c-I, d-IV

B) a-I, b-II, c-III, d-IV

C) a-IV, b-III, c-II, d-I

D) a-III, b-IV, c-I, d-II

प्रश्न 85:

असंगत कथन की पहचान करें :

A) BNS धारा 63 / पुरानी IPC 375 बलात्कार की परिभाषा से संबंधित है।

B) सामूहिक बलात्कार का प्रावधान BNS धारा 70 के तहत है जिसमें न्यूनतम 20 वर्ष से आजीवन कारावास का प्रावधान है।

C) पीछा करना (Stalking) BNS धारा 78 के तहत दंडात्मक है।

D) शून्य FIR केवल गैर-संज्ञेय अपराधों में दर्ज की जाती है।

प्रश्न 86:

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 (PWDVA) सिविल उपचारात्मक राहत प्रदान करता है जिसमें निवास का अधिकार और संरक्षण अधिकारी (PO) की भूमिका केंद्रीय होती है।

उपरोक्त परिच्छेद के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है?

A) PWDVA के तहत केवल आपराधिक कारावास का ही प्रावधान है।

B) साझा गृहस्थी में रहने का निवास अधिकार धारा 17 के तहत महिला को प्राप्त है।

C) संरक्षण अधिकारी (PO) की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है।

D) लिव-इन रिलेशनशिप PWDVA के दायरे में कभी नहीं आते हैं।

प्रश्न 87:

कथन I : लोक नीति सरकार का सुनियोजित और लक्ष्य-केंद्रित कोर्स ऑफ एक्शन है।

कथन II: भारतीय संविधान के DPSP (अनुच्छेद 36-51) लोक नीति के मार्गदर्शक सिद्धांत हैं।

कथन III: राजकोषीय प्रभाव आकलन वित्त विभाग द्वारा नहीं किया जाता है।

उपरोक्त में से कौनसा/कौनसे कथन/कथन समूह सत्य है :

- A) केवल 1 और 2
- B) केवल 2 और 3
- C) केवल 1 और 3
- D) केवल 1

प्रश्न 88:

कथन: किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत 16-18 आयु वर्ग के जघन्य अपराधों में प्रारंभिक आकलन का प्रावधान है।

कारण: CWC (बाल कल्याण समिति) विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के मामलों की सुनवाई करती है।

- A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या करता है
- B) A और R दोनों सत्य हैं परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं करता है
- C) A सत्य है परंतु R असत्य है
- D) A असत्य है परंतु R सत्य है

प्रश्न 89:

कथन: राजस्थान पुलिस 'सुरक्षा सखी' योजना सामुदायिक पुलिसिंग और जन-संवाद का प्रभावी मॉडल है।

निष्कर्ष I : सुरक्षा सखी योजना में समाज की महिलाओं/युवतियों को वालंटियर के रूप में जोड़ा जाता है।

निष्कर्ष II : 1090 महिला हेल्पलाइन अभय कमांड सेंटर से एकीकृत नहीं है।

- A) केवल निष्कर्ष I सत्य है
- B) केवल निष्कर्ष II सत्य है
- C) निष्कर्ष I और II दोनों असत्य हैं
- D) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 90:सुमेलित कीजिये

सूची I : विधिक / कल्याणकारी योजनाएं व हेल्पलाइन

- a) निर्भया फंड
- b) 1098 बाल हेल्पलाइन
- c) सखी वन स्टॉप सेंटर
- d) जन सूचना पोर्टल

सूची II : मुख्य वैधानिक/प्रशासनिक संदर्भ

I) संकटग्रस्त बच्चों की 24x7 आपातकालीन सहायता

II) गैर-लेप्सिबल कॉर्पस फंड जिससे महिला सुरक्षा अवसंरचना वित्तपोषित

III) जिला स्तर पर एकछत चिकित्सा, विधिक व परामर्श सुविधा

IV) 13 सितंबर 2019 से स्वतः प्रकटीकरण (proactive) डिजिटल पोर्टल

A) a-II, b-I, c-III, d-IV

B) a-I, b-II, c-III, d-IV

C) a-IV, b-III, c-II, d-I

D) a-III, b-IV, c-I, d-II

प्रश्न 91:

असंगत कथन की पहचान करें :

- A) तेजाबी हमला BNS धारा 124 के तहत न्यूनतम 10 वर्ष से आजीवन कारावास दंडात्मक है।
- B) दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत दहेज लेने पर न्यूनतम 5 वर्ष का कारावास है।
- C) दहेज मृत्यु BNS धारा 80 (पुराना IPC 304B) के तहत 7 वर्ष के भीतर होती है।
- D) धारा 498A समतुल्य BNS प्रावधान अजमानती नहीं बल्कि पूर्णतः जमानती अपराध है।

प्रश्न 92:

कथन: राजस्थान सौर ऊर्जा नीति के तहत भादला में वृहद सौर पार्क स्थापित किए गए हैं।

कारण: राजस्थान में 300 से अधिक धूप वाले दिन और अकृषि योग्य भूमि सौर ऊर्जा निवेश को आकर्षित करती है।

- A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या करता है
- B) A और R दोनों सत्य हैं परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं करता है
- C) A सत्य है परंतु R असत्य है
- D) A असत्य है परंतु R सत्य है

प्रश्न 93:

कथन I : बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत बालिका की न्यूनतम विवाह आयु 18 वर्ष है।

कथन II: बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016 के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बालकों का नियोजन पूर्णतः प्रतिबंधित है।

कथन III: POCSO Act 2012 लिंग-संवेदनशील नहीं बल्कि लिंग-तटस्थ है।

उपरोक्त में से कौनसा/कौनसे कथन/कथन समूह सत्य है :

- A) केवल 1 और 2
- B) केवल 2 और 3
- C) केवल 1 और 3
- D) केवल 1

प्रश्न 94:

असंगत कथन की पहचान करें :

- A) बाल कल्याण समिति (CWC) JJ Act धारा 27 के तहत गठित होती है।
- B) किशोर न्याय बोर्ड (JJB) में 1 न्यायिक मजिस्ट्रेट और सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं।
- C) राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में 1 अध्यक्ष और 10 सदस्य होते हैं।
- D) बाल विवाह को वयस्क होने के 2 वर्ष के भीतर शून्य घोषित कराया जा सकता है।

प्रश्न 95:

कथन: राइट टू हेल्थ अधिनियम आपातकालीन उपचार का अधिकार देता है।

निष्कर्ष I : आपातकाल में किसी भी अस्पताल में निःशुल्क इलाज की कानूनी बाधता है।

निष्कर्ष II : यह कानून केवल सरकारी अस्पतालों पर लागू होता है, निजी पर नहीं।

- A) केवल निष्कर्ष I सत्य है
- B) केवल निष्कर्ष II सत्य है
- C) निष्कर्ष I और II दोनों असत्य हैं
- D) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 96:

कथन I : जन सूचना पोर्टल 13 सितंबर 2019 को लॉन्च हुआ।

कथन II: यह पोर्टल स्वतः प्रकटीकरण (proactive disclosure) सिद्धांत पर कार्य करता है।

कथन III: इस पोर्टल पर सूचना देखने के लिए ₹10 शुल्क देना अनिवार्य है।
उपरोक्त में से कौनसा/कौनसे कथन/कथन समूह सत्य है :

- A) केवल 1 और 2
- B) केवल 2 और 3
- C) केवल 1 और 3

D) केवल 1

प्रश्न 97:

असंगत कथन की पहचान करें :

- A) आवाज़ अभियान महिलाओं/बच्चों के विरुद्ध मौन तोड़ने के लिए चलाया गया।
- B) गरिमा हेल्पलाइन वरिष्ठ नागरिकों/असुरक्षित वर्ग सुरक्षा हेतु है।
- C) 1090 हेल्पलाइन केवल बच्चों के लिए है और 1098 महिलाओं के लिए है।
- D) सखी केंद्र वन स्टॉप सेंटर के रूप में कार्य करते हैं।

प्रश्न 98:

कथन: POSH Act 2013 के तहत सुलह/समझौता प्रक्रिया में मौद्रिक समझौता या जबरन समझौता वर्जित है।

- कारण:** कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य सुरक्षित और गरिमापूर्ण माहौल देना है।
- A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या करता है
 - B) A और R दोनों सत्य हैं परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं करता है
 - C) A सत्य है परंतु R असत्य है
 - D) A असत्य है परंतु R सत्य है

प्रश्न 99:

कथन I : पोक्सो अधिनियम 2019 संशोधन के तहत गंभीर प्रवेशक लैंगिक हमले में मृत्युदंड का प्रावधान जोड़ा गया।

कथन II: पोक्सो के तहत मीडिया द्वारा बच्चे की पहचान उजागर करना दंडनीय है (धारा 23)।

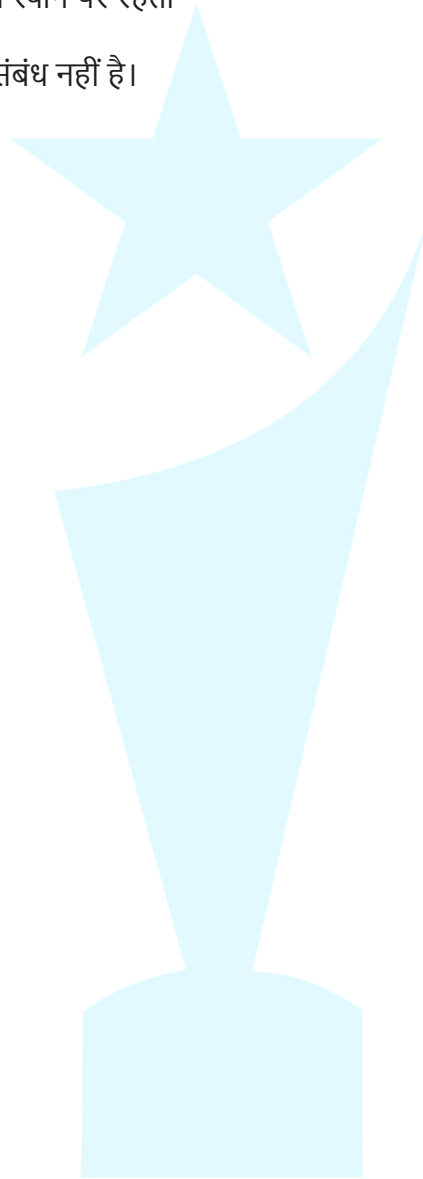
कथन III: पोक्सो मामलों का ट्रायल नियमित सिविल कोर्ट में बिना किसी समयावधि के होता है।
उपरोक्त में से कौनसा/कौनसे कथन/कथन समूह सत्य है :

- A) केवल 1 और 2
- B) केवल 2 और 3
- C) केवल 1 और 3
- D) केवल 1

प्रश्न 100:

सुशासन सूचकांक (GGI) में राजस्थान के प्रदर्शन के संदर्भ में कौन सा कथन तार्किक रूप से सर्वाधिक उपयुक्त है?

- A) GGI केवल न्यायिक सुरक्षा मापता है।
- B) कृषि, सामाजिक सुरक्षा और ई-गवर्नेंस सेवाओं के विस्तार से GGI स्कोर में सुधार हुआ है।
- C) राजस्थान GGI में हमेशा अंतिम स्थान पर रहता है।
- D) GGI का संघीय बजट से कोई संबंध नहीं है।



wincompete